बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-313
11/09/2019

मुख्यमंत्री के समक्ष पंचायती राज विभाग का प्रस्तुतीकरण

पटना, 11 सितम्बर 2019 :– 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष पंचायतों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिकोण से तैयार टैक्सेशन नियमावली का प्रस्तुतीकरण पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा द्वारा किया गया। प्रस्तुतीकरण के अवलोकनोपरांत मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग विभिन्न बिन्दुओं पर सरजमीन की स्थिति का अध्ययन कर नियमावली के प्रारूप को और व्यावहारिक तरीके से तैयार किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करें और इसके लिये मानव बल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से सम्पन्न कराया जाय। उन्होंने कहा कि चूँकि त्रि–स्तरीय पंचायतों को बड़ी राशि मिल रही है, ऐसी स्थिति में अभियंताओं की समुचित व्यवस्था हो, विशेषकर जिला स्तर पर मजबूत व्यवस्था करने के लिये प्रस्ताव गठित करने का निर्देश दिया।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 1435 नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी मिली है, जिसका निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा होगा। मुख्यमंत्री ने इन सभी नये स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों का कार्यारंभ एक साथ शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने हुये जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान में विलम्ब न हो, यह सुनिश्चित किया जाय और उनके मानदेय का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्तुतीकरण के क्रम में बताया गया कि हर जिले में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की जायेगी, इसके लिये जिला परिषद, भवन बनायेगी और इन संस्थानों में नियमित रूप से चुने गये प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। पंचायतों में स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करने के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने की भी व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और 50 हजार वार्डों में कार्यारंभ किया गया है। 27 हजार वार्डो में कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी गुणवता और रखरखाव पर विशेष जोर दिया और कहा कि जो योजना बने वह चलनी चाहिये। मुख्यमंत्री पक्की गली–नाली निश्चय योजना में 61 हजार वार्डों में काम पूर्ण हो गया है और शेष बचे हुये कार्य को 31 मार्च 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव पंचायती राज श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव वित्त श्री एस0 सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पंचायती राज विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

******